

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम० के० सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 257-एक/2011 -विरुद्ध आदेश दि. 28.10.2010
पारित द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर - प्रकरण क्रमांक
426 अ-19/ 2008-09 अपील

श्रीमती राधा देवी पत्नि हरीशकुमार

निवासी जोधाराम भवन

रावर्ट लायन, माधवनगर कटनी

---आवेदक

विरुद्ध

1- अपर आयुक्त, जबलपुर

2- म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर कटनी

3- अनुविभागीय अधिकारी कटनी

4- पटवारी ह०नं० 30ग्राम बोहता जिला कटनी

5- नायव तहसीलदार मुड़वारा ब्लाक कटनी

---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुशील मिश्रा)

(अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं)

आ दे श

(आज दिनांक 5-10-2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण
क्रमांक 426 अ-19/ 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक
28-10-2010 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की
धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि यह कि आवेदक ने कलेक्टर
कटनी के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि ग्राम बोहता स्थित भूमि
सर्वे क्रमांक 243/1 रकबा 23.82 हैक्टर में से 10 है. भूमि (आगे
जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पट्टे के आधार पर
कृषि करने हेतु आवंटित की जावे। कलेक्टर कटनी ने प्रकरण क०



14 अ-19/08-09 पंजीबद्ध किया एवं आवेदक के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच नायब तहसीलदार कटनी से एवं अनुविभागीय अधिकारी कटनी से कराई। जांचोपरांत आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 14.5.09 पारित किया एवं आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 426 अ-19/ 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 द्वारा अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

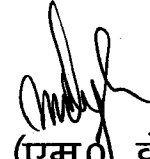
3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि की कृषि कार्य हेतु पट्टे पर देने मांग की गई है। कलेक्टर कटनी ने आवेदक के आवेदन की जांच नायब तहसीलदार से कराई है नायब तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन दिनांक 5-4-09 एवं पुर्नजांच प्रतिवेदन दिनांक 6.5.09 प्रस्तुत कर बताया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम हलका पटवारी ने भूमि उबड़-खाबड़ बताई है भूमि बेहड़ है एवं बन विभाग की सीमा से लगी हुई भूमि है। कलेक्टर कटनी ने आवेदक की सुनवाई कर वर्तमान में भूमि बन्टन पर रोक लगी होने के कारण पट्टे पर न देने का निर्णय लिया एवं आवेदक का आवेदन खारिज किया है। स्पष्ट है कि जब भूमि बन्टन



पर म०प्र०शासन द्वारा रोक लगाई गई है भूमि बन्टन नहीं की जा सकती और इन्हीं कारणों से आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 426 अ-19/ 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 से कलेक्टर के आदेश दिनांक 14.5.09 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य की जाती है। परिणामतः आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 426 अ-19/ 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 स्थिर रखा जाता है।



(एम० के० सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर